



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्रसापारण

### EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

#### PART I—Section 1

राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, वृहदतियार, जून 27, 1968/अषाढ 6, 1890

No. 124]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 1968/ASADHA 6, 1890

इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या को जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

#### RESOLUTION

New Delhi, the 28th June 1968

No. F. 1(6)PL480/68.—In response to recommendation number 34, contained in the Eleventh Report of the Estimates Committee (Fourth Lok Sabha), the Government of India promised to make arrangements for a study, by a small expert group, of the impact of PL-480 transactions on the monetary system. The Government of India have accordingly decided to set up a group with the following composition.

2. The group will consist of

Chairman

1. Dr. A. N. Khusro,  
Institute of Economic Growth,  
New Delhi.

*Members*

2. Shri D. H. Pai Panandikar,  
Senior Assistant Secretary,  
FICCI, New Delhi.

3. Shri K. C. Malhotra,  
Chartered Accountant, Delhi.

*Member-Secretary*

4. Shri M. R. Shroff,  
Director,  
Department of Economic Affairs,  
Ministry of Finance, New Delhi.

3. The terms of reference of the group will be as follows:—

- to examine the present system of recording the transactions relating to imports financed by U.S. PL-480 in the Budget of the Government of India and to suggest improvements, if any, with a view to bringing out clearly the implications of these transactions;
- to examine the impact of these transactions on the monetary system in terms of the effect on money supply, the ability of the authorities to control credit, etc.; and
- to examine the inflationary effect, if any, of these transactions on the economy.

4. The group will devise its own procedures and will submit its report to the Government of India within a period of three months from the date of this Resolution.

**ORDER**

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Chairman and the Members of the Committee.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

**A. T. BAMBAWALE, Jt. Secy.**

**वित्त मंत्रालय****(अर्थ विभाग)****संकल्प****नवी विस्ती, 26 जून, 1968**

संख्या 1 (6) पी० एल० 480/68.—ग्राहकलन समिति (चौथी लोक सभा) की ग्यारहवीं रिपोर्ट में की गयी मिकारिश संख्या 34 के उत्तर में भारत सरकार ने यह अन्वय दिया था कि मुद्रा-सम्बन्धी व्यवस्था पर पी० एल० 480 के लेन देनों का जो प्रभाव पड़ता है। ऐसे विशेषज्ञ दल द्वारा उसकी जांच कराने का प्रबन्ध किया

ज्ञानभाना। इसी के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित रूप में एक दल स्थापित करने का निष्पत्ति किया है।

2. दल में ये व्यक्ति होंगे :—

#### अध्यक्ष

1. डा० ए० एन० खुसरो, इंस्टिट्यूट आफ इकानामिक ग्रोथ, नयी दिल्ली

#### सदस्य

2. श्री डी० एच० पै पाण्डीकर, वरिष्ठ सहायक सचिव, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डलसंघ (एफ० आई० सी० आई०), नई दिल्ली।

3. श्री के० सी० मलहोत्रा, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट, दिल्ली।

#### सदस्य-सचिव

4. श्री एम० आर० श्राफ, निदेशक, अर्थ विभाग।

3. यह दल निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(i) भारत सरकार के बजट में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पी० एल० 480 द्वारा वित्त-पोषित आयातों के सम्बन्ध में होने वाले लेन-देनों को दर्ज करने की वर्तमान पद्धति की जांच करना और इन लेन-देनों के प्रभाव को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए यदि किसी सुधार की आवश्यकता हो तो, उसका सुझाव देना;

(ii) मुद्रा सम्बन्धी ध्यवरण पर पड़ने वाले, इन लेन-देनों के प्रभाव की, मुद्रा-उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव, अ० इन का नियन्त्रण करने की अधिकारियों की क्षमता आदि की दृष्टि से, जांच करना; और

(iii) यदि अर्थव्यवस्था पर इन लेन-देनों का मुद्रावाहृत्यकारी प्रभाव पड़ता हो तो उसकी जांच करना।

4. यह दल अपनी कार्यप्रणालियां स्वयं निश्चित करेगा और इस संकल्प की तारीख से तीन महीने के भीतर भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति इस समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के पास भेज दी जाय।

यह आदेश भी दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

अशोक बन्धावाले, संयुक्त सचिव।

